भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2868

(दिनांक 20.12.2023 को उत्तर के लिए)

विदेश में अध्ययन करने हेतु प्रायोजित करना

2868. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेश में लोक नीति और लोक प्रबंधन का अध्ययन करने अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रायोजित लोक सेवकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत में विशेषकर भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में लोक नीति और लोक प्रबंधन का शैक्षिक पारितंत्र पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या लोक सेवकों के बजाय आईआईएम और सरकारी लोक नीति संस्थानों के लोक नीति और लोक प्रबंधन संकाय को विदेश भेजना अधिक उपयुक्त नहीं है ताकि सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को और अधिक गहराई से और व्यापक रूप से विस्तारित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम में सुधार के लिए की जा रही नीति अथवा प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : विगत दो वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा किसी भी सिविल सेवक को विदेश में लोक नीति और लोक प्रबंधन के अध्ययन अथवा प्रशिक्षण लेने हेतु प्रायोजित नहीं किया गया है।

भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - मिशन कर्मयोगी की शुरूआत की है। इस पहल के तहत, केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता-विकास योजनाओं का निर्माण और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। सरकार द्वारा लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों को उन्नत बनाने तथा नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को सुगम बनाने हेतु निरंतर सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म आईगॉट कर्मयोगी भी प्रारंभ किया गया है। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों विशेष रूप से अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है ताकि पारस्परिक आधार पर प्रशिक्षण में इमर्सिव प्रायोगिक लर्निंग सामग्री, संकाय, अनुसंधान का समावेश किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) सिविल सेवकों के लिए लोक नीति और प्रबंधन पर दीर्घ और अल्प अवधि दोनों पाठ्यक्रम चला रहे हैं। आईआईएम संकाय विकास सहित वैश्विक संस्थानों के साथ मिलकर सहयोगात्मक कार्यक्रम भी चला रहे हैं ताकि उनके लोक नीति कार्यक्रमों में बेहतरीन वैश्विक सिद्धांतों और प्रथाओं का समावेश किया जा सके।

(ङ) : (क) से (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।